✸ 19th Year
✸ Issue: 279
✸ 17.02.2026 (TUESDAY)
✸ ROURKELA
✸ R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
✸ (Pages-6)
✸ Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

इमैनुएल मैक्रों का भारत दौरा! नई दिल्ली-पेरिस सामरिक रिश्तों के लिए अहम है यह यात्रा

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता):फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों सोमवार देर रात तीन दिन के दौरे पर भारत आएंगे, जिसमें वे इंडिया⁄द्ध इज़्पैज़्ट समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाइलेटरल मीटिंग करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मैक्रों का यह दौरा भारत-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के आपसी भरोसे और गहराई और दोनों पक्षों के बीच अपने रिश्तों को और गहरा करने के कमिटमेंट को दिखाता है।रूश्व ने पिछले हज़्ते एक बयान में कहा, इस दौरे के दौरान, दोनों नेता होराइजन 2047 रोडमैप में शामिल कई एरिया में बाइलेटरल कोऑपरेशन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

इसके अलावा, नेता आपसी हितों के रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें इंडो-पैसिफिक में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेता इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का मिलकर उद्घाटन करने के लिए मुंबई में भी होंगे, जिसे दोनों देशों में पूरे 2026 में मनाया जाएगा।फ्रांस वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण 114 राफेल फाइटर जेट्स (4.5 जेनरेशन) की खरीद का समझौता हो सकता है।मेक इन इंडिया पर जोर- डील के तहत 18 जेट ज़्लाई-अवे स्थिति में फ्रांस से आएंगे, जबकि शेष 96 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा।नौसेना की मजबूती- भारतीय नौसेना पहले ही 26 राफेल-रू का ऑर्डर दे चुकी है, और इस नई डील से वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।दुनिया की कुल त्नष्ठक्क का लगभग 60त्न हिस्सा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से आता है।

इस इलाके में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत और फ्रांस का गठबंधन रणनीतिक रूप से अनिवार्य हो गया है।फ्रांस की मौजूदगी- रीयूनियन और न्यू कैलेडोनिया जैसे फ्रांसीसी द्वीपों के कारण फ्रांस इस क्षेत्र में एक सक्रिय शक्ति है।सप्लाई चेन और स्थिरता- दोनों देश मिलकर सप्लाई चेन में विविधता लाने और समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा करेंगे। मैक्रों की इस यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित %इंडिया⁄द्ध इज़्पैज़्ट समिट 2026% है। तकनीकी सहयोग- प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैक्रों इस समिट में हिस्सा लेंगे, जो जिज़्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दिखाएगा।ईयर ऑफ इनोवेशन- दोनों नेता मुंबई में %इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026% का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य पूरे साल टेज़्नोलॉजी, रिसर्च और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी 2025 की फ्रांस यात्रा के ठीक एक साल बाद हो रहा है। बातचीत का मुज़्य आधार %होराइजन 2047% रोडमैप होगा, जो भारत और फ्रांस के बीच कूटनीतिक संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने (2047 में) तक के लिए एक दीर्घकालिक खाका तैयार करता है।मैक्रों के भारत दौरे से नई दिल्ली और पेरिस को इंडो-पैसिफिक में अपना सहयोग और बढ़ाने का मौका मिलेगा, यह एक अहम इलाका है जहाँ चीन लगातार अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ्रांस के सपोर्ट से, जिसके इस इलाके में रीयूनियन और न्यू कैलेडोनिया जैसे इलाके हैं, भारत इंडो-पैसिफिक में चीनी मौजूदगी का मुकाबला करना चाहता है।यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि इंडो-पैसिफिक दुनिया के कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडज़्ट (त्नष्ठक्क) का लगभग 60 परसेंट है, और भारत और फ्रांस इस इलाके को सुरक्षित करने और स्थिरता पक्का करने के लिए सप्लाइज़ चेन में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं।

महत्वाकांक्षा और जिमेदारी का संगम, एआई क्रांति में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि 1.4 अरब भारतीयों की शक्ति के साथ भारत वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में आ रहे बदलावों का नेतृत्व कर रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 'इंडिया एआई इज़्पैज़्ट एज़्सपो' 2026 के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति %महत्वाकांक्षा और दायित्व% दोनों का प्रतिबिंब है। मोदी की यह टिप्पणी उस दिन आई है जब वह यहां भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इज़्पैज़्ट एज़्सपो' 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं। 'इंडिया एआई इज़्पैज़्ट एज़्सपो' 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इज़्पैज़्ट समिट' के साथ किया जाएगा। मोदी ने 'एज़्स' पर एक पोस्ट में कहा, '' एआई पर चर्चा करने के लिए दुनिया को एक साथ ला रहे हैं! आज से, भारत दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इज़्पैज़्ट समिट की मेजबानी कर रहा है। मैं इस शिखर सज़्मेलन में दुनिया भर

के नेताओं, उद्योगपतियों, नवोन्मेषकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं।'' उन्होंने कहा कि शिखर सज़्मेलन का विषय ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' है, जो मानव-केंद्रित प्रगति के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग करने की ''हमारी साझा प्रतिबद्धता'' को दर्शाता है।

मोदी ने कहा कि आज एआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्यम सहित कई क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है। उन्होंने कहा कि 'एआई इज़्पैज़्ट समिट' एआई के विविध पहलुओं जैसे नवाचार, सहयोग, जिज़्मेदार उपयोग आदि पर वैश्विक चर्चा को समृद्ध करेगा। मोदी ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि शिखर सज़्मेलन के परिणाम एक प्रगतिशील, नवोन्मेषी और अवसर-उन्मुख भविष्य को आकार देने में सहायक होंगे।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''भारत की 1.4 अरब जनता की बदौलत हमारा देश एआई से आए परिवर्तन में अग्रणी स्थान पर है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से लेकर जीवंत स्टार्टअप तंत्र और अत्याधुनिक अनुसंधान तक, एआई में हमारी प्रगति महत्वाकांक्षा और जिज़्मेदारी दोनों को दर्शाती है। इससे पहले रविवार को मोदी ने भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे और कृत्रिम मेधा के वैश्विक केंद्र के रूप में पेश किया और कहा कि भारत दुनिया के डेटा को संभालने एवं प्रौद्योगिकी क्रांति की अगली लहर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

डीआरडीओ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिन-प्रतिदिन भारत की रणनीतिक शक्ति को मजबूत कर रहा है-राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता):रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई) को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बताते हुए वैज्ञानिकों से दशकों से चल रहे एयरो इंजन विकास कार्य को अगले पांच वर्षों में पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की रणनीतिक स्वायज़्ता महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में तेजी से महारत हासिल करने पर निर्भर करती है। बेंगलुरु स्थित गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान में बोलते हुए सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अधीन कार्यरत यह प्रतिष्ठान भारत की रणनीतिक क्षमता का आधार बन गया है। उन्होंने इसके वैज्ञानिकों को लगातार सफल परीक्षण करने और देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने का श्रेय दिया।

राजनाथ ने कहा और आगे कहा कि डीआरडीओ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिन-प्रतिदिन भारत की रणनीतिक शक्ति को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ प्रतिदिन एक के बाद एक सफल परीक्षण करता रहता है। हमें प्रतिदिन डीआरडीओ की उपलज़्धियों के बारे में सुनने को मिलता रहता है। एक परीक्षण की चर्चा समाप्त होते ही दूसरी उपलज़्धि की खबर आ जाती है। दूसरे शज़्दों में, डीआरडीओ आज भारत की रणनीतिक क्षमता का आधार बन गया है।

एयरो इंजन में स्वदेशी क्षमता की आवश्यकता पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि जहां एक इंजन विकसित करने में आमतौर पर 20-25 साल लगते हैं, वहीं भारत को अब पांच साल में वह हासिल करना होगा जिसे अन्य देशों को हासिल करने में दशकों लग गए हैं।

उन्होंने कहा कि अगर एक इंजन विकसित करने में 25 साल लगते हैं, तो भारत की वर्तमान स्थिति, हमारी रणनीतिक आवश्यकताओं और हमारी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, आपको यह मान लेना चाहिए कि आपके 20 साल पहले ही बीत चुके हैं और अब आपके पास केवल 5 साल बचे हैं। यह कोई चौंकाने वाली या आश्चर्य की बात नहीं है; यह एक चुनौती है। हमें इन 5 वर्षों में वह हासिल करना है जो अन्य देश 20 वर्षों में करते हैं। यहीं पर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

सबरीमाला : 9 जजों की संविधान पीठ 7 अप्रैल से करेगी सुनवाई

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता): केरल के पहाड़ी तीर्थस्थल सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की वैधता से संबंधित पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू करेगी। पीठ ने पक्षों को लिखित दलीलें प्रस्तुत करने के लिए 14 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है और सुनवाई 22 अप्रैल तक समाप्त होने की उज़्मीद है। भारत के मुज़्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि इस मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसकी संरचना मुज़्य न्यायाधीश द्वारा एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी।यह मामला सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, जिसने सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश की अनुमति दी, और उस लंबे समय से चली आ रही प्रथा को पलट

दिया जिसके तहत मासिक धर्म वाली उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता था। 2018 का फैसला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से सुनाया था। इस फैसले के बाद केरल भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों और संगठनों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, लेकिन इस मुद्दे का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। न्यायालय ने संकेत दिया कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं और संवैधानिक अधिकारों से संबंधित व्यापक कानूनी प्रश्नों की जांच के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता है।

निर्वाचन आयोग का बड़ा एज़्शन! पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारी निलंबित, गंभीर कदाचार के लगे आरोप

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता): निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों के बीच एक कड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में सात अधिकारियों कोगंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के लिए सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

निलंबित किए गए ये सभी सात अधिकारी सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (श्वक्रह्र) के रूप में कार्यरत थे।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन अधिकारियों ने मतदाता सूची तैयार करने की वैधानिक प्रक्रिया में निज़्नलिखित अनियमितताएं कीं-अधिकारों का दुरुपयोग- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्ढक्र) से जुड़े वैधानिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल। बूथ स्तरीय अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और उनके सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो मतदाता सूची अद्यतन करने और चुनाव कराने में सहायता के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं।आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मुज़्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग के जरिए इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें और इसकी जानकारी आयोग को दें।

निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पहले से ही टकराव की स्थिति बनी हुई है।यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। आयोग का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वार्थ नहीं, जुड़ाव ही समाज की पहचान, गोरखपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भगवत ने दिया सद्भाव का मंत्र

गोरखपुर १६/०२ (संवाददाता): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भगवत ने रविवार को गोरखपुर दौरे के दौरान एक सामाजिक सद्भाव सज़्मेलन में भाग लिया। यह कार्यक्रम संघ के शताज़्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया था। संघ सूत्रों के अनुसार, आरएसएस प्रमुख ने बाबा गंभीर नाथ सभागार में आयोजित सामाजिक सद्भाव सज़्मेलन में प्रमुख नागरिकों और स्वयंसेवकों को संबोधित किया। सज़्मेलन से पहले, उन्होंने दीप प्रज्वलित करके संघ की 100 वर्षीय यात्रा और%पंच परिवर्तन% विषय पर आधारित एक प्रदर्शनी का

उद्घाटन किया।इसके बाद, भगवत ने प्रदर्शनी का दौरा किया और संघ के शताज़्दी वर्ष के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के गोरख प्रांत द्वारा संगठन की शताज़्दी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित सामाजिक सद्भाव% सज़्मेलन को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि समाज की पहचान परस्पर जुड़ाव से होती है, न कि स्वार्थ से। उन्होंने कहा कि कई देशों में रिश्तों को लेन-देन के रूप में देखा जाता है। हमारे देश में मानवीय रिश्ते अपनेपन की भावना पर आधारित होते हैं।उन्होंने आगे कहा कि भारत सद्भावना और सामाजिक सद्भाव का वैश्विक केंद्र है। देश की सज़्यतागत विचारधारा लेन-देन वाले रिश्तों के बजाय एकता और आपसी जुड़ाव की भावना में निहित है। भारत की विविधता पर प्रकाश डालते हुए भागवत ने कहा कि रीति-रिवाजों, पहनावे और परंपराओं में अंतर विभाजन पैदा नहीं करते, ज़्योंकि अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता ही हमारी पहचान है।

दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर तय किए आरोप, अब चलेगा मुकदमा

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता): सोमवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के सीबीआई मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुज़्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए, आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। यह मामला रेलवे ग्रुप डी की नौकरियां उज़्मीदवारों को ज़मीन के बदले दिलाने के कथित अपराध से संबंधित है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय

किए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जब तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति न दी जाए। मीसा भारती ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है। 9 जनवरी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

आरोप तय करते समय, सीबीआई की विशेष अदालत ने टिप्पणी की थी, प्रथम दृष्टया, लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इच्छुक नौकरी चाहने वालों से अचल संपज़ि हासिल करने की साजिश रची गई थी।

अदालत ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे। अदालत ने मुज़्य कार्मिक अधिकारियों (सीपीओ) और रेलवे अधिकारियों सहित 52 आरोपियों को बरी कर दिया। कार्यवाही के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो गई। सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप तय किए गए थे।

विशेष न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आर्द्रपत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट संकेत मिलता है। बहस के दौरान, लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि जमीन के बदले नौकरी का मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उज़्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गईं। बिक्री विलेख हैं जो दर्शाते हैं कि जमीनें पैसे देकर खरीदी गईं।

विविध समाचार

अब एआई बनेगा भारत की नई शक्ति! भारत मंडपम से नरेंद्र मोदी ने किया तकनीकी क्रांति का शंखनाद

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी राजधानी के भारत मंडपम में इंडिया एआई इज़्पैज़्ट एज़्सपो 2026 का उद्घाटन किया। यह एज़्सपो 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इज़्पैज़्ट समिट के साथ आयोजित किया जाएगा और इसे कृत्रिम बुद्धिमज़्ा के व्यावहारिक उपयोग को प्रदर्शित करने वाले एक राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है, जो नीति निर्माण, नवाचार और व्यापक कार्यान्वयन को एक ही मंच पर लाएगा। 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 क्षेत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार

भाग ले रहे हैं।

इंडिया एआई इज़्पैज़्ट समिट 2026 के दौरान जियो एआई पवेलियन में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस के क्षेत्र में कंपनी के एआई-आधारित परिवर्तन का प्रदर्शन किया। 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई नेता एआई इज़्पैज़्ट समिट 2026 के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए। एआई इज़्पैज़्ट समिट तीन मूलभूत स्तंभों या %सूत्रों% पर आधारित है- लोग, ग्रह और प्रगति। इंडिया एआई इज़्पैज़्ट एज़्सपो में 30 देशों के 300 से अधिक प्रदर्शकों के 10 से अधिक विषयगत पवेलियनों में भाग लेने की उज़्मीद है।

भारत-एआई इज़्पैज़्ट समिट 2026 का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमज़्ा के लिए प्रभाव-उन्मुख और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जिसमें मापने योग्य सामाजिक और आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। यह शिखर सज़्मेलन तीन मूलभूत स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें %सूत्र% कहा जाता है - एक संस्कृत शज़्द जिसका अर्थ है मार्गदर्शक सिद्धांत या आवश्यक सूत्र जो ज्ञान और कर्म को आपस में जोड़ते हैं। ये सूत्र परिभाषित करते हैं कि किस प्रकार बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सामूहिक लाभ के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है।

इंडिया एआई इज़्पैज़्ट समिट 2026 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप केंद्रित और परिणामोन्मुखी परिणाम दे रहा है। यह समिट सरकार और उद्योग जगत में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक एआई तैनाती, नीतिगत सामंजस्य और संस्थागत समन्वय को बढ़ावा दे रहा है। यह शासन और नियामक ढांचों को मजबूत कर रहा है, एआई-आधारित औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्रीय तैयारियों का आकलन कर रहा है और कौशल विकास एवं कार्यबल परिवर्तन को गति दे रहा है। यह समिट एआई अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है और एआई पारिस्थितिकी तंत्र के जिज़्मेदार, समावेशी और नवाचार-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग के बीच स्थायी साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।

बीजापुर में एक इनामी समेत पांच नज़्सली गिरफ्तार

बीजापुर१६/०२ (संवाददाता): छज़्ीसगढ़ के नज़्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने एक इनामी समेत पांच नज़्सलियों को गिरज़्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के उसूर थाना क्षेत्र में मारूड़बाका गांव के जंगल में सुरक्षाबलों ने पांच नज़्सलियों ..नारायण भण्डारी ;45द्धए धरमा काका ;21द्धए नीला काका ;25द्धए किस्टा ध्रुवा ;30द्ध और रामबाबू पूनेम ;26द्ध को गिरज़्तार किया है। उन्होंने बताया कि नज़्सली नारायण मारूड़बाका दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन का अध्यक्ष है

जहाजों व बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए होगा ज़्यूरो ऑफ पोर्ट सिज़्योरिटी का गठन, अमित शाह ने दिए निर्देश

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित निकाय, ज़्यूरो ऑफ पोर्ट सिज़्योरिटी (बीओपीएस) के गठन हेतु एक बैठक बुलाई है।

बैठक के दौरान, शाह ने देश भर में एक मजबूत बंदरगाह सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिया कि सुरक्षा उपायों को जोखिम-आधारित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें कमजोरियों, व्यापार क्षमता, स्थान और अन्य प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखा जाए। इस बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री उपस्थित थे। गृह मंत्रालय (रूv्र) के बयान के अनुसार, नवगठित व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत बोर्ड ऑफ पोर्ट्स (क्चश्चस्) को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाएगा।

बयान में आगे कहा गया है कि महानिदेशक की अध्यक्षता वाला यह ज़्यूरो बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय (रूश्चस्ह्ल्ल) के तत्वावधान में कार्य करेगा और जहाजों एवं बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित नियामक एवं निगरानी कार्यों के लिए उज़्रदायी होगा। गृह मंत्रालय ने बताया इस ज़्यूरो का गठन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ज़्यूरो (बीसीएएस) की तर्ज पर किया जा रहा है। बीओएस का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी (वेतन स्तर-15) करेंगे। एक वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि के दौरान, महानिदेशक जहाजरानी (डीजीएस/डीजीएमए) बीओएस के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि बंदरगाह सुरक्षा बल (बीओएस) सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के समय पर विश्लेषण, संग्रह और आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही बंदरगाह के आईटी बुनियादी ढांचे को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए एक समर्पित विभाग भी शामिल होगा। बंदरगाह सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के रूप में नामित किया गया है, जो बंदरगाहों के लिए सुरक्षा आकलन करने और सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने के लिए जिज़्मेदार है।

शीतकालीन सत्र में पारित विधेयक भारत को बनाएंगे विकसित भारत, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का दावा

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता):केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विधेयक भारत को विकसित भारत के सपने की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम पर हुई चर्चाओं ने देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि 2025 का शीतकालीन सत्र एक बहुत ही सक्रिय सत्र है। इस सत्र में पारित विधेयक करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और भारत को एक %विकसित% राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा अत्यंत फलदायी और महत्वपूर्ण रही। वंदे मातरम पर व्यापक चर्चाओं के माध्यम से हमने देशभक्ति की भावना को एक बार फिर से जागृत किया है।

रिजिजू ने कहा कि चुनावी सुधारों पर हुई चर्चा के बाद आम जनता के लंबे समय से चले आ रहे सवालों के जवाब पूरी स्पष्टता के साथ मिल गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर भारत के चुनाव आयोग और चुनावी सुधारों पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लेकिन संसद के दोनों सदनों में चुनावी सुधारों पर हुई बहस के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया। चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली पर आरोप लगाने वालों का भी पर्दाफाश हो गया। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहली बार था जब चुनाव आयोग और चुनावी सुधारों पर अलग-अलग चर्चा हुई, और भविष्य में होने वाली किसी भी चर्चा के लिए केंद्र सरकार की तत्परता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और चुनावी सुधारों पर पहली बार अलग-अलग चर्चाएँ हुईं। इससे पता चलता है कि सरकार चर्चाओं के लिए कितनी तत्पर है... इस चर्चा के बाद कोई भ्रम नहीं रह गया है। विपक्ष को इसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके अलावा, वीबी-जी राम जी विधेयक के पारित होने पर बोलते हुए, रिजिजू ने खुशी व्यक्त की और भ्रष्टाचार के अंत और अधिक पारदर्शिता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जी राम जी विधेयक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसे भ्रष्टाचार को रोकने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए लाया और पारित किया गया है। सरकारी सुधार ही आगे बढ़ने का रास्ता हैं, एज़्सप्रेस की तरह, और यह रुकेगा नहीं। मैं इस सत्र से बहुत संतुष्ट हूँ; कामकाज बहुत अच्छे से हुआ है। इस बीच, शुक्रवार को संसद ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक पारित कर दिया, जिसे लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा ने भी स्वीकार कर लिया।

प्रदूषण पर चर्चा ज़्यों नहीं? जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता): कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हाल ही में समाप्त हुआ संसद का शीतकालीन सत्र सरकार की इस मुद्दे पर व्यवस्थित बहस करने की अनिच्छा के कारण प्रभावी रूप से प्रदूषण सत्र में तज़्दील हो गया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रमेश ने कहा कि संसद में सरकार की प्रतिक्रिया से उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसमें उन्होंने प्रदूषण और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया।कांग्रेस नेता ने कहा कि यह शीतकालीन सत्र नहीं, बल्कि प्रदूषण सत्र था। मैं उस समय स्तज़्ध रह गया जब सरकार ने कल संसद में यह कहकर जवाब दिया कि प्रदूषण और फेफड़ों की समस्याओं के बीच कोई संबंध नहीं है।

रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में, विशेष रूप से उज़्र भारत में, जहां प्रदूषण का स्तर हज़्तों से गंभीर बना हुआ है, बिगड़ती वायु गुणवज़्ा पर विस्तृत चर्चा की बार-बार मांग की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी। हम लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस चाहते थे। कांग्रेस नेता ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि विपक्ष द्वारा व्यवधान डालने से प्रदूषण पर बहस नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि विपक्ष की मांगों के बावजूद लोकसभा को इस मुद्दे पर चर्चा किए बिना अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दुर्भाग्य से, लोकसभा में ही सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई।

उन्होंने कहा कि सज़ाधारी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए, रमेश ने जोर देकर कहा कि चर्चा न होने की जिज़्मेदारी सरकार की है। सरकार का यह बयान कि कांग्रेस के कारण प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी, गलत है। मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं।

पाकिस्तान के नज़्शेकदम पर चल रहा बांग्लादेश, पड़ोसी देश की स्थिति पर बोले गिरिराज सिंह

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता):बांग्लादेश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें कम से कम चार लोग घायल हो गए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को इस घटना को एक दुखद घटना बताया। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि यह एक दुखद घटना है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों के लिए यह विशेष रूप से चिंताजनक है। ऐसी घटनाएं गंभीर प्रश्न उठाती हैं और इन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।बांग्लादेश की स्थिति पर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह खेदजनक है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के नज़्शेकदम पर चल रहा है और देश में ममता बनर्जी जैसी नेता हैं जो भारत को बांग्लादेश में बदलना चाहती हैं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी इस स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद

खेदजनक है कि बांग्लादेश, जिस देश की स्थापना में भारत ने मदद की, अब हमारे खिलाफ रुख अपना रहा है। नेपाल और श्रीलंका की मौजूदा स्थिति, और इससे पहले पाकिस्तान में हुई घटनाएं, कूटनीतिक जिज़्मेदारी के महत्व को उजागर करती हैं।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में 'घटनाक्रम के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ है'। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति पर उनका नियंत्रण है। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय स्थिति से उचित ढंग से निपट रहे हैं तथा वे उसी अनुरूप जवाब देंगे। राज्यसभा सदस्य ने संवाददाता सज़्मेलन में बांग्लादेश की स्थिति से संबंधित प्रश्नों का उज़्र देते हुए कहा, बांग्लादेश में कट्टरपंथ और चरमपंथ कैंसर की तरह फैल रहा है। सभी सही सोच वाले लोगों को इस खतरे से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा,1980 के दशक से ही बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें अपनी जड़ें फैला रही हैं।

राहुल गांधी ने जर्मनी के पूर्व चांसलर से की मुलाकात, मैन्युफैक्चरिंग पर की अहम चर्चा

नयी दिल्ली १६/०२ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ के साथ दोपहर के भोजन पर चर्चा की। यह मुलाकात जर्मनी की उनकी पांच दिवसीय यात्रा के दौरान हुई। इससे पहले, मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जर्मनी के ज़्यूनिख स्थित बीएमडज़्ल्यू वर्ल्ड ज़्यूजियम का दौरा किया, जहां उन्होंने जर्मन ऑटोमोबाइल निर्माता के साथ साझेदारी में विकसित टीवीएस 450 सीसी मोटरसाइकिल सहित भारतीय इंजीनियरिंग की उपलज़्धियों को देखकर प्रशंसा व्यक्त की। यात्रा के दौरान, उन्होंने बीएमडज़्ल्यू द्वारा निर्मित विभिन्न कारों के प्रदर्शन को देखते हुए आगंतुकों से बातचीत की। राहुल गांधी

ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि भारत को उत्पादन शुरू करने की जरूरत है; उत्पादन किसी भी देश की सफलता की कुंजी है। हमारा विनिर्माण क्षेत्र घट रहा है; वास्तव में इसे बढ़ना चाहिए। पार्टी द्वारा साझा किए गए वीडियो में गांधी ने कहा, हम बीएमडज़्ल्यू फैज़्ट्री गए थे - शानदार अनुभव रहा - और मुझे यह देखकर विशेष रूप से खुशी हुई कि उनके पास 450 सीसी की बाइक, टीवीएस है, और मुझे लगता है कि यह अच्छा प्रदर्शन करेगी। यह देखकर अच्छा लगा कि यहां भारतीय ध्वज लहरा रहा है। इस बीच, जर्मनी की अपनी पांच दिवसीय यात्रा के दौरान बर्लिन हवाई अड्डे पर पहुंचने पर राहुल गांधी का भारतीय प्रवासी कांग्रेस (आईओसी) द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बर्लिन के हर्टी स्कूल को संबोधित किया, जहां उन्होंने नेतृत्व, लोकतंत्र और वैश्विक जिज़्मेदारी पर बात की। तेजी से बदलती दुनिया में नेतृत्व, लोकतंत्र और वैश्विक जिज़्मेदारी पर विचार करते हुए गांधी ने कहा, लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं है - यह जुड़ाव, जिज़्मेदारी और जवाबदेही की एक निरंतर प्रक्रिया है।छात्रों, विद्वानों और शिक्षाविदों के एक समूह को संबोधित करते हुए गांधीजी ने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक अनुभवों से अंतर्दृष्टि साझा की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान घोषित इस पांच दिवसीय यात्रा ने भाजपा नेताओं की व्यापक आलोचना को जन्म दिया। उनका आरोप है कि उनकी बार-बार की यात्राएं भारतीय कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाती हैं। जर्मनी की यह यात्रा इस महीने की 20 दिसंबर तक जारी रहने वाली है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

अन्न दान से लेकर विद्या दान, हिंदू धर्म में बताए गए हैं दान के 4 प्रकार

हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में दान को केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति और मानवता की सेवा का सबसे बड़ा मार्ग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, दान से न केवल पुण्य फल मिलता है, बल्कि यह जीवन के कष्टों और ग्रह दोषों से भी मुक्ति दिलाता है। मुख्य रूप से दान के चार सर्वश्रेष्ठ प्रकार बताए गए हैं।

आहार दान (अन्न दान)

भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी सेवा है। अन्न दान को एक पुण्यकारी सेवा माना गया है क्योंकि यह तात्कालिक रूप से व्यक्ति को तृप्ति प्रदान करता है। इसे जीवन दान के समान माना गया है।

औषधि दान (स्वास्थ्य दान)

बीमार व्यक्ति को दवाइयां उपलब्ध कराना या उसकी चिकित्सा में मदद करना औषधि दान कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार, औषधि दान अन्न दान से भी बेस्ट है क्योंकि यह व्यक्ति को कष्टों और रोगों से मुक्ति दिलाकर उसे राहत प्रदान करता है।

ज्ञान दान (विद्या दान)

शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना सबसे उत्तम दान है। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना या ज्ञानवर्धक पुस्तकों को बांटना व्यक्ति का भविष्य संवारता है। यह दान न केवल दानकर्ता को यश दिलाता है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

अभय दान (सुरक्षा दान)

किसी डरे हुए व्यक्ति या जीव को भयमुक्त करना और उसकी रक्षा करना अभय दान है। जैन धर्म में इसे दानों का राजा कहा गया है। किसी के प्राण बचाना या ऐसा आचरण करना कि आपकी वजह से कोई भयभीत न हो, महानतम दान की श्रेणी में आता है।

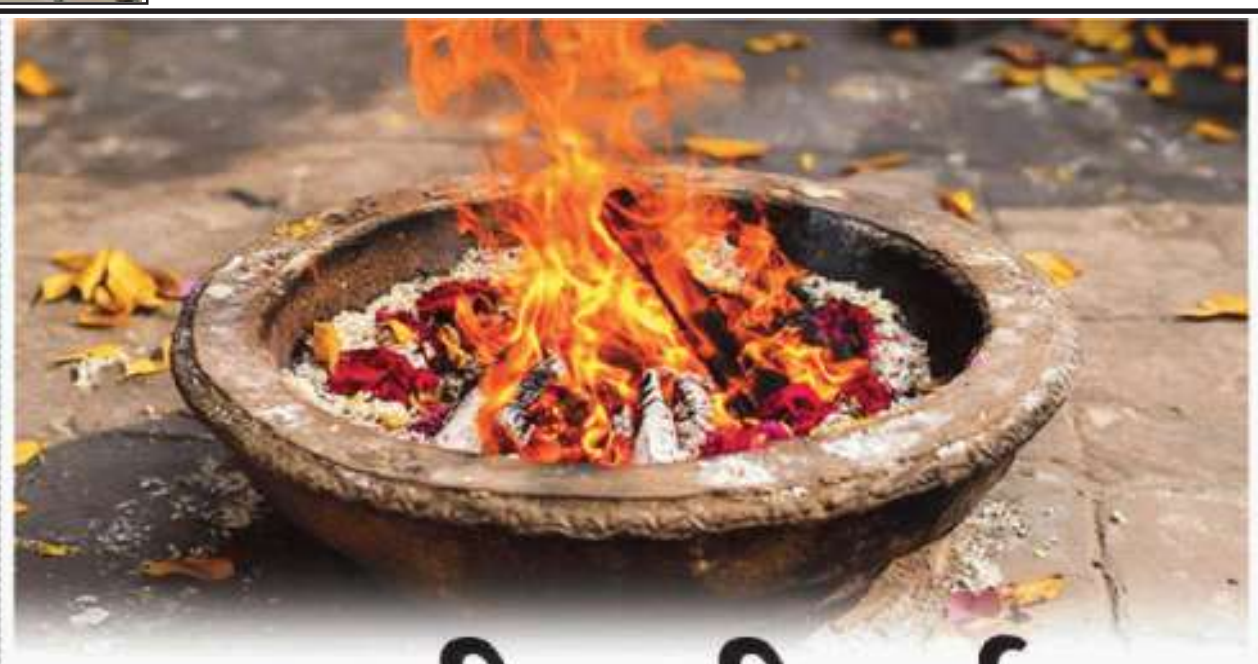

हवन की बची हुई राख का क्या करें?

इन उपायों से बदल सकती है किस्मत

हिंदू धर्म में पूजा से जुड़ी किसी भी सामग्री का विशेष महत्व होता है और उन सभी सामग्रियों को बहुत पवित्र माना जाता है। यही नहीं पूजा के बाद बची हुई सामग्रियों को भी विशेष स्थान दिया जाता है। ऐसे ही घर में जब भी हवन होता है तब हम उसकी बची हुई राख का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं।

हवन को अत्यंत पवित्र और शुभ कर्म माना गया है। हवन के दौरान अग्नि में डाली गई समिधा, जड़ी-बूटियां और घी वातावरण को शुद्ध करते हैं और आस-पास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि हवन की राख का क्या करना चाहिए? क्या आप इसे नदी में प्रवाहित कर सकती हैं या इससे कुछ अन्य उपाय किए जा सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि यदि आप हवन की बची हुई राख से ज्योतिष के कुछ उपाय आजमाती हैं तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आइए ज्योतिर्विद पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी से जानें हवन की बची हुई राख का क्या करना चाहिए और इससे आप कौन से ज्योतिष उपाय कर सकती हैं।

अत्यंत पवित्र मानी जाती है हवन की राख

ज्योतिष में हवन की राख को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह अग्नि देव के साक्षात संपर्क में आती है। इसमें कई पवित्र लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और इन्हें प्रज्वलित करने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर होती है। यही नहीं हवन में सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की क्षमता होती है। इसी वजह से आपको कभी भी हवन की राख को बिना सोचे-समझे हुए कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। इसको आपको हमेशा सही स्थान पर ही रखना चाहिए।

मुख्य द्वार पर लटकाएं हवन की राख की पोटली

घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको हवन के समापन के बाद इसकी राख को घर के मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कना चाहिए, जिससे घर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। अगर आप मुख्य द्वार पर हवन की राख छिड़कती हैं तो मुख्य द्वार से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो सकता है। इस उपाय से आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और किसी भी बुरी शक्ति का नाश होता है। आप इस राख को किसी पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका सकती हैं, इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी।

हवन की तिजोरी या अलमारी में रखें

अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक समस्याएं चली आ रही है, तो आपको घर में हवन करने के बाद इसकी बची हुई राख को घर में तिजोरी वाले स्थान पर रख देना चाहिए। आप इस राख को किसी लाल कपड़े में बांधकर घर में पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपके जीवन की कोई भी आर्थिक समस्या दूर हो सकती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस उपाय से आप पैसों की फिजूलखर्ची को भी रोक सकती हैं।

घर के गार्डन में डालें हवन की राख

हवन की राख को आप घर के गार्डन में इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप ये राख किसी ऐसे स्थान पर डालें जहां किसी का पैर नहीं पड़ता है तो ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इसे घर के बाहर पीपल या नीम के पेड़ के पास रखती हैं तो इसके शुभ फल मिलते हैं।

घर के कोनों में करें छिड़काव

यदि आपके घर में बिना वजह तनाव, कलह-कलेश बने रहते हैं तो आप घर में हवन करने के बाद इसकी राख को घर के चारों तरफ छिड़कें। इस उपाय से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बिना वजह कलेश दूर होते हैं। आप एक चुटकी राख को पानी में मिलाएं और इसका छिड़काव घर के चारों तरफ करें। इससे आपके जीवन में शांति बनी रहती है और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। शास्त्रों के अनुसार, हवन की राख को श्रद्धा के साथ माथे या गले पर लगाने से सभी रोगों में राहत मिल सकती है। इसलिए आपको कभी भी हवन की राख को कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए बल्कि इसे श्रद्धा पूर्वक किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित करना चाहिए।

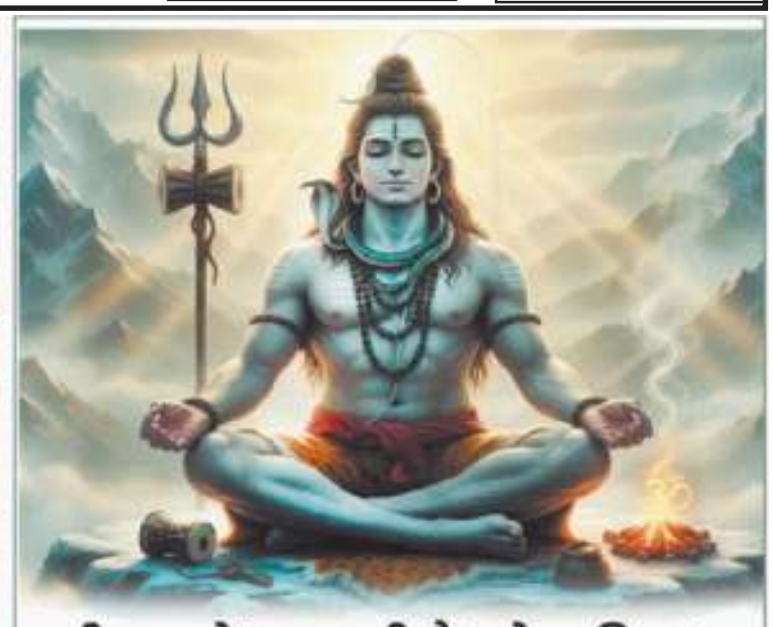

जीवन में बढ़ रही हैं परेशानियां?

इस स्तोत्र के नियमित पाठ से मिलेगी हर कष्ट से मुक्ति, सही नियम और समय

हिंदू धर्म में भगवान शिव को आशुतोष माना गया है यानी वे जो मात्र एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कई मंत्र और चालीसा प्रचलित हैं, लेकिन शास्त्रों में परमेश्वर स्तुति स्तोत्र को विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि यह स्तोत्र न केवल जीवन की बाधाओं को दूर करता है।

हिंदू धर्म में भगवान शिव को आशुतोष माना गया है यानी वे जो मात्र एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कई मंत्र और चालीसा प्रचलित है, लेकिन शास्त्रों में परमेश्वर स्तुति स्तोत्र को विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि यह स्तोत्र न केवल जीवन की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि साधक को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता से भर देता है।

क्या है इस स्तोत्र का आधार

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, परमेश्वर स्तुति स्तोत्र महादेव के उस कल्याणकारी और विराट स्वरूप को समर्पित है, जो सृष्टि का आधार है। आध्यात्मिक जानकारों का मानना है कि जब व्यक्ति खुद को संकटों से घिरा हुआ पाता है, तब इस स्तोत्र का पाठ एक अमोघ शक्ति की तरह काम करता है। यह भक्त के अंतर्मन की शुद्धि कर आत्मविश्वास को जागृत करने में सहायक होता है।

नियमित पाठ से मिलने वाले चमत्कारी लाभ

ज्योतिष और धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्तुति के नियमित जाप से कई दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं-

मानसिक तनाव से मुक्ति - इस स्तोत्र की विशिष्ट ध्वनियां और शब्द विन्यास मस्तिष्क को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में प्रभावी माने जाते हैं।

नकारात्मकता का नाश - घर और कार्यस्थल पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए इसे अत्यंत प्रभावशाली माना गया है।

पाप शमन और मोक्ष - पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धापूर्वक किया गया यह पाठ अनजाने में हुए पापों के प्रभाव को कम करता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाता है।

कार्य सिद्धि - जीवन में आ रही अनचाही बाधाएं और रुकावटें महादेव की कृपा से दूर होने लगती हैं।

पाठ की सही विधि और नियम

किसी भी स्तोत्र का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसे विधि-विधान से किया जाए। परमेश्वर स्तुति स्तोत्र के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है -

समय और स्वच्छता - ब्रह्म मुहूर्त या सुबह स्नान के बाद स्वच्छ सफेद या केसरिया वस्त्र पहनकर पाठ करना सबसे उत्तम है।

पूजन सामग्री - भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें।

विशेष दिन - वैसे तो इसका पाठ प्रतिदिन फलदायी है, लेकिन सोमवार, प्रदोष व्रत या शिवरात्रि के दिन इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है।

पूर्णता - पाठ संपन्न होने के बाद महादेव को बेलपत्र और जल अर्पित करें, यह पूजा की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है।

भारत के इन 5 मंदिरों का प्रसाद भूलकर भी घर न लाएं, हो सकते हैं बड़े नुकसान

भारत को मंदिरों और देवताओं की भूमि के रूप में सदियों से सराहा जाता रहा है। यहां के हर स्थान पर कोई न कोई प्रसिद्ध मंदिर जरूर है। हर स्थान पर कोई ना कोई ऐसा मंदिर भी होता है जिसकी अपनी लंबी कहानी होती है। यही नहीं उन मंदिरों की रहस्यमई कथाओं के साथ उनसे जुड़े कुछ तथ्य भी जरूर होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही देश के कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी कहानी के साथ उससे जुड़ी कुछ बातें भी हैं जो हैरान कर सकती हैं। उन्हीं में से कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके लिए यह प्रचलित है कि यदि आप वहां दर्शन के लिए जा रही हैं तो भूलकर भी आपको उन स्थानों का प्रसाद अपने घर में नहीं लाना चाहिए। मान्यता यह भी है कि यदि आप इन मंदिरों का प्रसाद घर लेकर आती हैं तो इससे आपके घर में भी घटनाएं हो सकती है और कुछ नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। आइए जानें भारत के उन अनोखे मंदिरों के बारे में जिनसे आप शायद अनजान होंगी।

मेहंदीपुर बालाजी

हनुमानजी को समर्पित मेहंदीपुर बालाजी का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से प्रेत बाधाएं समाप्त होती है और जो लोग बुरी शक्तियों से पीड़ित होते हैं, उनको इस मंदिर में दर्शन करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस मंदिर में यदि कोई व्यक्ति बूंदी के लड्डू का भोग लगाता है तो उसकी बाधाएं दूर होती हैं। इसी स्थान पर भैरव बाबा को भी उड़द दाल और बावल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में यदि कोई आपको प्रसाद दे तो उसे ग्रहण न करें और न ही मंदिर का प्रसाद घर लाएं, अन्यथा जीवन में समस्याएं आ सकती हैं।

काल भैरव मंदिर

काल भैरव मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्त मदिरा का भोग लगाते हैं। यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां यह परंपरा प्रचलित है कि यहां जो मदिरा भोग में चढ़ती है उसका भोग ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही इसे घर लाना चाहिए। यदि आप भूलकर भी इस प्रसाद को घर लाती है तो आपके घर में कुछ अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं।

कामख्या देवी मंदिर

कामख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह भारत का एक मात्र मंदिर है जहां माता कामाख्या की योनि की पूजा उनके मासिक धर्म के दौरान की जाती है। यहां साल में एक बार 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है और इस दौरान मंदिर के भीतर किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है यही नहीं यदि कोई इस मंदिर का प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके जीवन में कुछ अशुभ घटनाएं हो सकती हैं।

नैना देवी मंदिर

नैना देवी मंदिर हिमाचल में मौजूद है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, यहां प्रसाद के रूप में दी जाने वाली चीजें विशेष अनुष्ठान के बाद केवल माता को अर्पित की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को आपको मंदिर परिसर में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। आपको भूलकर भी इस मंदिर का प्रसाद मंदिर से बाहर या घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि यदि आप इस प्रसाद को मंदिर परिसर में ही ग्रहण कर लेती हैं तो इसके कोई अशुभ प्रभाव नहीं होते हैं।

कोटिलिंगेश्वर मंदिर

कोटिलिंगेश्वर मंदिर कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है और इस मंदिर में एक करोड़ शिवलिंगों की स्थापना की गई है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का प्रसाद भक्तों को केवल प्रतीकात्मक रूप से ही ग्रहण करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि आपको कभी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी वजह से इस मंदिर में प्रसाद न तो ग्रहण करना चाहिए और न ही इसे मंदिर से बाहर लाना चाहिए।

कलिंग समाचार

संपादकीय

मंगलवार 17 फरवरी 2026

अमेरिका से व्यापार समझौते में सब गोलमाल!

अमेरिका से व्यापार समझौते पर मोदी सरकार बड़ी कामयाबी की डींगे हांक रही है, लेकिन धरातल पर नजर आ रहा है कि वह हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को लेकर जो प्रेस वार्ता की, उसमें न केवल देश के हितों से विरोधाभास नजर आया, बल्कि यह भी साफ दिखा कि सरकार के भीतर ही अब तक सारी बातें स्पष्ट नहीं हैं और दो मंत्रियों के बीच गेंद को एक–दूसरे के पाले में डालने का खेल चल रहा है। तीन दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा गया कि व्यापार समझौते पर ताज़ा जानकारी क्या है? तो उन्होंने कहा था कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछिए। वो ही इसको देख रहे हैं। वहीं पीयूष गोयल से जब शनिवार को रूस से तेल खरीद पर स्थिति साफ करने को कहा गया तो श्री गोयल ने कहा कि विदेश मंत्रालय से पूछिए। पत्रकारों को इस तरह एक–दूसरे के पास टरकाने का क्या मतलब है। क्या सरकार के मंत्रियों में आपस में बात नहीं होती या सबको अपने हिस्से का श्रेय चाहिए या कि सरकार को खुद ही नहीं पता है कि आखिर में डील में क्या–क्या है और क्या–क्या नहीं है। जैसे पीयूष गोयल ने इससे पहले कहा था कि 3–4 दिनों में भारत–यूएस ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने शुक्रवार रात को ही इसकी घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि भारत में तब तक किसी मंत्रालय के पास ट्रेड डील के फ्रेमवर्क की जानकारी नहीं थी। इसके बाद पीयूष गोयल और पीएम मोदी और अन्य मंत्रियों ने इस पर ट्वीट करना शुरू किया। बहरहाल, पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में किन क्षेत्रों को अमेरिका में निर्यात पर शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा, उनमें रत्न और आभूषण, हीरे, दवाइयां, जेनेरिक और फार्मा उत्पाद, स्मार्टफोन शामिल हैं। इसके अलावा बताया गया कि कई कृषि उत्पादों पर पहले 50 प्रतिशत तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इनमें मसाले, चाय, कॉफी, खोपरा, नारियल, नारियल तेल, वनस्पति तेल, सुपारी, ब्राजील नट्स, काजू, चेस्टनट, एवाकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, मशरूम, सब्जियों की पौध जड़ें, जौ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस समझौते में किसी भी ऐसे उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील वस्तुओं को समझौते से बाहर रखा गया है। भारत में किसी भी प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ यह व्यापार समझौता किसानों, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों के हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा।इस तरह का स्पष्टीकरण देने का मतलब ही है कि कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। वैसे भी भारतीय किसानों ने चेतावनी दे ही दी है कि उनके खिलाफ सरकार गई तो फिर आंदोलन पर उतर जाएंगे। शायद इसलिए सरकार अभी से उन्हें समझाने में लगी है। वैसे पीयूष गोयल के अनुसार, इस समझौते से श्रम–प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और फुटवियर, खिलौने तथा रत्न एवं आभूषण के निर्यात में तेजी आएगी। इससे बड़ी सं या में महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश में उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। मतलब बेरोजगारी दूर करने का नया झुनझुना थमाया गया है। पीयूष गोयल ने ये तो बताया कि क्या निर्यात होगा, लेकिन आयात क्या होगा, और उसके लिए धन का इंतजाम कैसे होगा, ये नहीं बताया। समझौते के मुताबिक भारत ने अगले पांच सालों में अमेरिका से पांच सौ बिलियन डॉलर के उत्पाद खरीदने का वादा किया है, यानि भारत को अपना आयात 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। हमारा आयात शुल्क 40–42 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग सौ बिलियन डॉलर प्रति वर्ष हो जाएगा। कमज़ोर रुपये और नाजुक अर्थव्यवस्था के साथ, यह पैसा कहां से आएगा? यह समझौता बराबरी का कम और ब्लैकमेलिंग का ज्यादा लगता है। इस बारे में कांग्रेस ने सही कहा कि दोस्ती बराबरी की होती है। ऐसे में जब दोस्त आपको रोज 2 थप्पड़ मारे और आपके कुछ कहने पर एक थप्पड़ कम कर दे।

बजट : दूर–दूर तक नहीं दिखती विकास की राह

डॉ. इंदिरा हिरवे

कई जरूरी समस्याएं हैं जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है। सबसे पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (माइक्रो, मीडियम एंड स्माल इंटरप्राइजेस– एमएसएमई) भारत में धन और आय की बढ़ती असमानताओं और जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। एमएसएमई से भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (ईयू–भारत एफटीए)के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उ मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका भाषण बहुत लंबा और मुद्दों पर प्रकाश डालने वाला कतई नहीं था। यह एक थका हुआ सा प्रयास मात्र प्रतीत होता है।

लंबा होने के बावजूद भाषण व्यापक रणनीति या असं य योजनाओं और सं याओं के अंतर्निहित समग्र दृष्टिकोण में गोता नहीं लगाता। इन अर्थों में हमने कई विषयों को सुना लेकिन विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय उथल–पुथल और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसके व्यापक प्रभावों के समय में आवश्यक उन महत्वपूर्ण दिशात्मक मुद्दों पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। इसके बजाय वित्त मंत्री ने अलग–अलग योजनाओं पर खर्च की बारीकियां बताने में बहुत अधिक समय बिताया। नतीजा यह हुआ कि हम बजट की बड़ी तस्वीर के क्रियान्वयन के बारे में सुनने से चूक गए।

भारत–अमेरिका डील के अनकहे पहलू मु य व्यय पूंजीगत वस्तुओं पर है। बजट में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर 17.15 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। यह सकारात्मक है। कैपेक्स भविष्य के लिए बनाता है और एक ऐसा निवेश है जो दीर्घकालिक भौतिक संपत्ति प्रदान करने के लिए है। यह एक गुणक प्रभाव देता है और निजी निवेश को आकर्षित कर सकता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहित करता है। जहां तक बजट व्यय का संबंध है, कुल व्यय में सबसे अधिक हिस्सा ब्याज भुगतान या ऋण सेवा 26.20 प्रतिशत पर है। इसके बाद रक्षा (14.67 प्रश), परिवहन (11.2 प्रतिशत) और नागरिक पेंशन (5.54 प्रतिशत) है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर (क्रमशः2.60,1.96 तथा 1.17 फीसदी) खर्च कम हैं।

विकसित भारत पर जोर देने का स्वागत किया जाना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि भारत पूरी तरह से विकसित हो? फिर भी, इस विकास की दिशा के संदर्भ में बड़े सवाल बने हुए ह

एक ऐसे भारत में विकास की प्रकृति क्या होनी चाहिए जहां असमानता की दर ऊंची है, स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं जिन्हें बार–बार

उजागर किया गया है। विचार करें कि शिक्षा पर कुल प्रतिशत (केंद्र और राज्य का संयुक्त व्यय) सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.3 और स्वास्थ्य पर केवल 1.5 फीसदी है। यह चौंकाने वाले आंकड़े हैं, अविश्वसनीय है।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अस्वस्थ और कम शिक्षित आबादी के साथ देश कभी भी विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। पिछले दशक में हमारा अनुभव बताता है कि जब तक दोनों क्षेत्रों को सरकार के प्रबंधन के तहत नहीं रखा जाता तब तक शिक्षा और स्वास्थ्य आबादी के निचले 40 प्रतिशत तक नहीं पहुंच सकता। इसके बावजूद हाल के वर्षों में मामले विपरीत दिशा में चले गए हैं और बजट इस पर साहसिक रुख अपनाने में असमर्थ रहा है या तैयार नहीं है। ध्यान दें कि स्वास्थ्य के निजीकरण को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति वास्तव में उपचार की लागत बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को कम करने के लिए काम करती है, न कि इसे विस्तारित करने के लिए है। अस्पतालों में निजी इक्विटी निवेश के उदय में यह सबसे अधिक दिखाई देता है।

पिछले साल के बजट की तुलना में इस चालू वर्ष में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च बहुत कम है। यानी इन योजनाओं को सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता। इन योजनाओं पर बजट में वृद्धि मामूली है। कोई भी यह कह सकता है कि मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कुल मिलाकर केंद्र की प्रायोजित योजनाओं पर खर्च लगभग स्थिर रहा है। यह उन योजनाओं की तस्वीर दिखाता है जो इरादे के मुताबिक या प्रचार के अनुरूप नतीजे नहीं दे सकतीं और न ही देंगी।

विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साक्ष्य–आधारित उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक प्रोत्साहन, वैज्ञानिक सोच और लोगों के सही दृष्टिकोण के निर्माण के प्रयासों में पर्याप्त निवेश नहीं होगा तो देश इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगा? भारत अनुसंधान और विकास में अन्य उभरते देशों से बहुत पीछे है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह अल्प निवेश एक नकारात्मक सोच है। वास्तविक साक्ष्य से पता चलता है कि अनुसंधान पर जो पैसा खर्च किया गया है वह आधुनिक विज्ञान की स त मांगों और जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता।

एक उचित आवंटन और चेतावनी भरी टिप्पणी के साथ यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि यह पैसा कहां जाएगा, तभी इस गिरावट को ठीक करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा और भी कई जरूरी समस्याएं हैं जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है। सबसे पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (माइक्रो, मीडियम एंड स्माल इंटरप्राइजेस– एमएसएमई) भारत में धन और आय की बढ़ती असमानताओं और जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। एमएसएमई से भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (ईयू–भारत एफटीए)के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उ मीद है। यूरोपीय संघ–भारत एफटीए के अमलीकरण के संबंध में कई चुनौतियां हैं। ये विशेष रूप से गैर–टैरिफ बाधाओं से संबंधित हैं– एफटीए के लिए आवश्यक है कि माल का उत्पादन मानक गुणवत्ता का होना चाहिए। साथ ही माल का उत्पादन बाल श्रम के उपयोग के बिना होना चाहिए, पर्यावरणीय मानदंडों का स ती से पालन किया जाना चाहिए; और इसी तरह की अन्य शर्तें हैं। आज हमारे ज्यादातर एमएसएमई इन मानदंडों का पालन नहीं करते। हालांकि बजट में इन क्षेत्रों में मदद के लिए कुछ भी शामिल नहीं किया गया है।

धन और आय की असमानताओं पर इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। इन व्यापक असमानताओं के साथ विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सरकार के अनुसार जलवायु परिवर्तन सौर ऊर्जा तक ही सीमित है। यद्यपि इसमें व्यापक प्रदूषण, लगभग सभी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का अनुभव और हिमालय की बिगड़ती स्थितियों सहित वनों की कटाई भी शामिल है– बजट में इन आपात स्थितियों को संबोधित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, खासकर युवाओं की।

बजट में इस ज्वलंत समस्या का ज़िक्र तक नहीं है। संक्षेप में, बजट में या तो हमारी गंभीर समस्याओं को बाहर रखा गया है या उन्हें एक तरह की दिखावटी सेवा दी गई है। ऐसे बजट से देश कभी भी सतत विकास को हासिल नहीं कर सकता। रास्ता सही नहीं है और उस हद तक विकास के सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे।

मिशन–500 या कूटनीतिक आत्मसमर्पण?

अरुण कुमार डनायक

एक और गंभीर पहलू रूसी तेल आयात का है। इसके दूरगामी कूटनीतिक और आर्थिक परिणाम होंगे। रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध या सीमित प्रतिबद्धता से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति और रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। इससे यह संदेश भी जाएगा कि भारत वैश्विक दबावों के सामने स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ हो रहा है। मैंने भारत–अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार वार्ता पर लगातार पांच आलेख लिखे— जो विभिन्न समाचार पत्रों में समय–समय पर प्रकाशित हुए। भारत–अमेरिका डील का दावा राष्ट्रपति ट्रप ने ट्रुथ सोशल पर किया। उसके बाद, मेरे पूर्व आलेखों में व्यक्त आशंकाएं और विश्लेषण एक–एक कर सत्य सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। इस व्यापार समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस %रणनीतिक साझेदारी% को सरकार उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है, उसके भीतर कई अनसुलझे प्रश्न दबे हैं, जिन्हें अब सार्वजनिक बहस के बिना टाला नहीं जा सकता।

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इस समझौते को वंडरफुल बताते हुए मिशन–500 का अहम पड़ाव मान रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं को शून्य की ओर ले जाने, 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी सामान खरीदने और रूसी तेल आयात बंद करने पर सहमति जताई है। भारतीय सरकार ने इन दावों की पुष्टि नहीं की और केवल अमेरिकी टैरिफ में 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने का स्वागत किया।

पारदर्शिता की इस कमी पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि सार्वजनिक डोमेन में केवल ट्रंप के बयान हैं, कोई लिखित या संयुक्त वक्तव्य नहीं। योगेंद्र यादव ने पूछा है कि क्या सरकार ने अमेरिकी दबाव में आकर कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्र में दरवाज़े खोल दिए हैं। संसद सत्र के दौरान सदन को विश्वास में लिए बिना किए गए ऐसे समझौते लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

सबसे अधिक चिंता कृषि क्षेत्र को लेकर है। अमेरिकी कृषि मंत्री ने कहा है कि यह समझौता अमेरिकी किसानों के लिए है और उनके उत्पादों को भारत के विशाल बाज़ार में प्रवेश मिलेगा। अमेरिका में कृषि को भारी सब्सिडी मिलती है; ऐसे सस्ते उत्पाद यदि भारतीय मंडियों में उतरें, तो घरेलू किसानों की कीमतें और आय दबाव में आ सकती हैं। यह वही कृषि क्षेत्र है जिसे सरकार अब तक %रेड लाइन% बताती रही थी। हालांकि सरकार और कुछ विशेषज्ञ यह संकेत दे रहे हैं कि गेहूं, चावल और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली सुरक्षित हैं। अन्य क्षेत्रों जैसे डेयरी, पोल्ट्री और प्रोसेस्ड फूड पर दबाव बढ़ सकता है।

कृषि पर प्रभाव काफी हद तक विवरणों पर निर्भर करेगा। यदि संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित रहते हैं, तो नुकसान कम होगा; अन्यथा, किसान आंदोलन जैसी चुनौतियां संभव हैं। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जब तक साझा दस्तावेज़ सामने न आए, इसे अंतिम सौदा नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

मैंने पहले भी कहा था कि कृषि क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है और भारत को आयात से संरक्षण देना चाहिए, ताकि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार सुरक्षित रहें। साथ ही, भारत और अमेरिका के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से निर्यात अवसर, तकनीकी सहयोग और रोजगार जैसे फायदों से इनकार नहीं किया जा सकता, और इससे भारतीयों की खाद्य समस्याओं का समाधान भी संभव है। अब हमें इंतजार करना होगा कि सरकार इस डील की पूरी जानकारी सार्वजनिक करे, ताकि सभी संदेह और अनिश्चितताएं दूर हो सकें। उद्योग जगत को तो इस समझौते का स्वागत करना ही था और उसने सरकार के सुर से सुर मिलाने में विल ब नहीं किया है। आर्थिक दृष्टि से सरकार और उद्योगपति इस समझौते को सकारात्मक बता रहे हैं और उ मीद जताई जा रही है कि, इससे भारत की जीडीपी वृद्धि में लगभग 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। गोल्डमैन सेंसैक्स ने भी व्यापार नीति में अनिश्चितता घटने और निवेश भावनाओं में सुधार की बात कही है। शेयर बाज़ार में तेजी, रुपये की मजबूती और विदेशी पूंजी के लौटने के संकेत भी इसी उ मीद से जुड़े हैं। लेकिन इन सकारात्मक अनुमानों के बीच यह प्रश्न बना हुआ है कि लाभ किसे और किस कीमत पर मिलेगा। निर्यातकों और बड़े उद्योगों को राहत मिल सकती है, पर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोखिम बढ़ता दिख रहा है। पहले के उच्च अमेरिकी टैरिफ से भारत का निर्यात घटा था, लेकिन आयात बढ़ने से व्यापार घाटा और गहराने की आशंका भी है।

इस समझौते का एक अपेक्षाकृत कम चर्चित, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू प्रवासी भारतीयों से जुड़ा है। टैरिफ में कमी से अमेरिका में भारतीय वस्तुएं— जैसे वस्त्र, मसाले, दवाइयां और उपभोक्ता सामान—कुछ सस्ती हो सकती हैं। इससे प्रवासी भारतीयों की बचत बढ़ेगी और भारत को भेजी जाने वाली रेमिटेंस पर इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। यह लाभ वास्तविक है, लेकिन इसका दायरा सीमित है ।

एक और गंभीर पहलू रूसी तेल आयात का है। इसके दूरगामी कूटनीतिक और आर्थिक परिणाम होंगे। रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध या सीमित प्रतिबद्धता से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति और रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। इससे यह संदेश भी जाएगा कि भारत वैश्विक दबावों के सामने स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ हो रहा है।

अमेरिकी तेल महंगा है और उसकी ढुलाई लागत भी अधिक है। ऐसे में आयात संरचना बदलने से मुद्रास्फीति और चालू खाते पर दबाव बढ़ सकता है, और इससे आम उपभोक्ता तथा समग्र अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। यह प्रश्न एक बार फिर अनुत्तरित है कि भारत की नीतिगत घोषणाएं वॉशिंगटन से क्यों होती हैं, संसद से क्यों नहीं? अब असली सवाल यह नहीं रह गया है कि चेतावनियां दी गई थीं या नहीं, बल्कि यह है कि सरकार ने उन्हें अनसुना क्यों किया? क्या यह जल्दबाज़ी थी, राजनीतिक छवि–निर्माण की हड़बड़ी थी, या यह मान लिया गया था कि बाद में संसद और जनता को समझा लिया जाएगा? जब तक समझौते का पूरा, लिखित और लागू करने योग्य पाठ सार्वजनिक नहीं होता और उस पर संसद में बहस नहीं होती, जश्न मनाना आधारहीन है। सरकार भले ही इसे उपलब्धि बता रही हो, लेकिन संसद, किसान और नीति–जगत इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक जल्दबाज़ी और लोकतांत्रिक अपारदर्शिता का परिणाम मान रहे हैं। यह समझौता मोदी सरकार की कूटनीतिक असफलता का प्रतीक है, जहां ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के सामने भारत झुकता दिखाई देता है। यह समय उत्सव का नहीं, बल्कि सतर्कता और जवाबदेही का है—क्योंकि दांव पर केवल व्यापार नहीं, बल्कि भारत की कृषि, ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता है।

चुनाव सुधार पर अहम चर्चा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के कृत्य को अंजाम देकर सबसे बड़ा देशविरोधी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ द आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत की अवधारणा को नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी वोट चोरी के इल्जाम लगाते हुए कई सबूत भी पेश कर चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों पर भाजपा ने हमेशा चुनाव आयोग का बचाव किया है और खुद चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों का तार्किक जवाब देने की जगह इन पर फेक का ठप्पा लगाकर खारिज कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र इतने उथलेपन के साथ नहीं चल सकता कि विपक्ष के आरोपों को गलत कहकर अपनी जि मेदारी से बरी हुआ जाए। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर मतदाता सूची में तथाकथित शुद्धिकरण की जरूरत अभी क्यों पड़ी है। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने देश के 12 और राज्यों में मतदाता सूची का एसआईआर करवाया है, आज यानी 11 तारीख को एसआईआर के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। पहले यह मियाद 4 दिसंबर तक थी, लेकिन जब चुनाव आयोग को खुद यह समझ आया कि इतनी जल्दी करोड़ों मतदाताओं की सूची फिर से तैयार नहीं हो सकती तो तारीख आगे बढ़ाई गई।

हालांकि विपक्ष पहले ही इस जल्दबाजी पर सवाल उठा रहा था। एसआईआर का मामला अदालत में भी है, लेकिन चुनाव आयोग ने न बिहार चुनाव के वक्त विपक्ष की आपत्तियों और लोगों की तकलीफों पर ध्यान दिया न अब दे रहा है। इस बीच एसआईआर के काम में लगे कई बीएलओज़ की अकाल मौत या गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें आ चुकी हैं। मगर चुनाव आयोग ने यह माना ही नहीं कि बीएलओज़ पर काम का या कुछ खास समुदायों के वोट काटने का दबाव है। एसआईआर से जुड़े ऐसे कई सवालों पर विपक्ष सदन में भी चर्चा चाहता था ताकि देश को इस बारे में सरकार का आधिकारिक नजरिया पता चले। पिछले मानसून सत्र में विपक्ष की इस मांग को सरकार ने टाल दिया था, लेकिन शीतकालीन सत्र में सरकार अपनी जिद पर टिक नहीं पाई। एसआईआर तो नहीं लेकिन चुनाव सुधार के नाम पर चर्चा के लिए सरकार राजी हुई। अब इसमें विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनके बेतुके जवाब भाजपा दे रही है।

विविध समाचार

5100 नवजन्मी बेटियों की लोहड़ी : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सशक्त संदेश : डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़ / जालंधर १६/०२ (संवाददाता):। बेटी बचाओदृबेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को और सुदृढ़ करते हुए गांव घुड़का के जोहल फार्म में 5100 नवजन्मी बेटियों के सम्मान में लोहड़ी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर, पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती राज लाली गिल, तथा पंजाब एग्री फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन मंगल सिंह बस्सी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने बेटी बचाओदृबेटी पढ़ाओ के संदेश को समाज तक और अधिक मजबूती से पहुंचाया। इस अवसर पर पंजाब सरकार की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए कहा कि 5100 नवजन्मी बेटियों की लोहड़ी मनाना समाज में बेटियों के प्रति बदलती सकारात्मक सोच का स्पष्ट प्रतीक है। उन्होंने नवजन्मी बेटियों के माता–पिता को लोहड़ी पर्व की बधाई दी और उन्हें सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना बदलती सामाजिक सोच की वास्तविक पहचान है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बच्चियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कई जनहितकारी योजनाएं लागू कर रही है, ताकि हर बेटी को सम्मान, समानता और आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी प्रयासों के साथ–साथ सामाजिक संस्थाओं और गांव स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी ही बेटी बचाओ अभियान को सफल बना सकती है। इस प्रकार के सामूहिक आयोजन नई पीढ़ी में समानता, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस पहल के लिए जोहल फार्म सेवा सोसायटी और कार्यक्रम से जुड़े अन्य सहयोगियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक प्रयास बेटियों के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पंजाब में सीएम चेहरा नहीं बनाएगी कांग्रेस, इंचार्ज बघेल बोले सबसे बड़ा चेहरा होगा सिर्फ राहुल गांधी

बठिंडा १६/०२ (संवाददाता): 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में सीएम फेस बनने की रेस शुरू होने से पहले ही रुक गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी व छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस का कोई भी सीएम चेहरा नहीं होगा। बठिंडा पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में चेहरा सिर्फ राहुल गांधी का ही होगा। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। भूपेश बघेल ने कहा कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, सब चेहरा हैं लेकिन सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था। उसके पहले सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। अभी भी हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल, विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता खुद को सीएम फेस समझने लगे थे। लेकिन कांग्रेस इंचार्ज के इस बयान के बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं को झटका लगा है। हालांकि राजा वड़िंग और रंधावा पहले ही सीएम चेहरे का दावा छोड़ चुके हैं। बघेल का सीधे तौर पर कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित न करने की बात कहना 2022 के चुनाव से सबक लेना है। तब चन्नी और नवजोत सिद्धू की लड़ाई से कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई। इस बार हाईकमान नहीं चाहता कि सीएम कुर्सी को लेकर झगड़ा शुरू हो। पंजाब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इन दिनों बिना किसी विवाद या खुली बयानबाजी के मुख्यमंत्री चेहरे की अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हैं। वर्ष 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाए जाने के बाद चन्नी को प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। हालांकि उन्हें मात्र तीन महीने का कार्यकाल मिला, लेकिन उस दौरान लिए गए उनके फैसले कांग्रेस को लगातार सुर्खियों में ले आए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा हालात में पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में नजर आती है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने तरनतारन उपचुनाव और जिला परिषददृब्लॉक समिति चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन फिलहाल वह कांग्रेस के बराबर की स्थिति में नहीं दिखता। भाजपा की बात करें तो उसका वोट शेयर भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसकी पकड़ अभी कमजोर बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के लिए पंजाब एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, क्योंकि यह उन राज्यों में शामिल है जहां भाजपा की राजनीतिक मौजूदगी सीमित है।

पंजाब सीएम सेहत बीमा योजना की लांचिंग टली, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कारण

चंडीगढ १६/०२ (संवाददाता): पंजाब सरकार की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, जो पहले 15 जनवरी को लॉन्च होनी थी, जो अब 22 जनवरी को लॉन्च की जाएगी। योजना के लॉन्च में यह एक सप्ताह की देरी जत्थेदार साहिब द्वारा मुख्यमंत्री को समन किए जाने के कारण हुई है। यह जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने फतेहगढ़ साहिब में दी। वह यहां योजना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना के औपचारिक शुभारंभ से पहले इसका ट्रायल रन किया जाएगा, ताकि किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक खामी को दूर किया जा सके। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। योजना का लक्ष्य करीब 3 करोड़ लोगों को कवर करना है।

सरकार की कोशिश है कि हर पात्र नागरिक को सेहत बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए दो क्राइटेरिया है। एक तो आधार कार्ड पंजाब का होना चाहिए और वोटर कार्ड पंजाब का होना चाहिए। जो बच्चे है, उनका डिपेंटेंड कार्ड होना चाहिए।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि हमें कई अन्य सोर्स से भी पैसे आने है। सरकार 1200 से 1500 करोड़ खर्च करेगी तो इससे लोगों का फायदा होगा। इससे लोगों को इमरजेंसी केयर मिलेगी। सेहत मंत्री ने कहा कि यह योजना बहुत अच्छी है। जैसे फ्री बिजली की योजना दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शुरू की। इसे आगे पंजाब में सीएम भगवंत मान ने बढ़ाया।

अमृतसर में सरपंच हत्याकांड में शामिल 2 शूटर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, 5 मददगार भी पकड़े, गैंगस्टर दासुवाल से थी रंजिश

चंडीगढ़ १६/०२ (संवाददाता): पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी से जुड़े सरपंच जरमल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले को लेकर सोमवार को पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी साझा की। डीजीपी के अनुसार, सरपंच हत्याकांड में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 2 की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के रायपुर से, 2 मोहाली से और 3 तरनतारन से की गई है। डीजीपी ने बताया कि रायपुर से पकड़े गए सुखराज सिंह निवासी तरनतारन और कर्मजीत सिंह निवासी गुरदासपुर ने ही सरपंच पर गोलियां चलाई थीं। इसके अलावा जोबनजीत सिंह समेत दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है वहीं आज सुबह पुलिस ने कुलविंदर सिंह किंदा, अरमानदीप सिंह और हरदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि रायपुर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को वहां की स्थानीय अदालत में पेश कर 14 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। इसके बाद उन्हें हवाई मार्ग से पंजाब लाया जा रहा है। डीजीपी ने यह भी खुलासा किया कि इस हत्या की साजिश विदेश में बैठे एक हैंडलर ने रची थी। सरपंच जरमल सिंह की गैंगस्टर प्रभ दासुवाल के साथ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। डीजीपी गौरव यादव ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि कोई पंजाब में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा, तो पंजाब पुलिस उसे देश या विदेश कहीं भी छोड़ेगी नहीं। उल्लेखनीय है कि तरनतारन क्षेत्र के रहने वाले सरपंच जरमल सिंह की 4 जनवरी को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अमृतसर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। वारदात के बाद दोनों शूटर छत्तीसगढ़ फरार हो गए थे और रायपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां छिपे हुए थे। रविवार को रायपुर और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

आतिशी के फर्जी वीडियो में गुरुओं का नाम जोड़ कर भाजपा ने की बेअदबी : भगवंत सिंह मान

बठिंडा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के दिल्ली विधानसभा के वीडियो से छेड़छाड़ करने के लिए भाजपा की कड़ी निंदा की और इसे पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की नीच साजिश करार दिया। धर्मनिरपेक्ष पंजाब सरकार ऐसे मंसूबों को सफल नहीं होने देगी, यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो को एडिट करके इसमें जानबूझकर गलत शब्दावली शामिल की गई है, जो सिख धर्म की घोर बेअदबी है। साथ ही उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि आतिशी ने अपने बयान में कहीं भी "गुरु" शब्द नहीं बोला। भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह झूठी वीडियो क्लिप विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं नहीं है और भाजपा चंडीगढ़, बीबीएमबी तथा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर पंजाब विरोधी मानसिकता से चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्षी दलों के नेता नीच राजनीति करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा न होने के कारण इस झूठ का बचाव करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। बठिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शुरू से ही भाजपा ने फिर्कापरस्ती, बंटवारा और नफरत की राजनीति की है और इसी के हिस्से के रूप में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के मद्देनजर भाजपा ने पंजाब में लोगों को सांप्रदायिक लकीरों पर बांटने के लिए इस एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ करके इसमें आपत्तिजनक शब्दावली शामिल की है। यहां तक कि फॉरेंसिक जांच में भी स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि 'आप' नेता ने कहीं 'गुरु' शब्द बोला ही नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना भगवा पार्टी की पुरानी रणनीति है और इस कार्रवाई ने सिख संगत की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है क्योंकि वीडियो से छेड़छाड़ करके उन्होंने सिखों की बेअदबी की है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नीच हरकत करने वालों को उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ के बारे में पूरी स्पष्टता हो गई है क्योंकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सदन की कार्यवाही में यह शब्द कहीं भी बोले नहीं दिखाई देते। भाजपा नेता कपिल मिश्रा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिस नेता ने सोशल मीडिया पर यह एडिटेड (छेड़छाड़ वाला) वीडियो अपलोड किया था, उसे अपने कुकर्मों के नतीजे भुगतने पड़ेंगे और पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ सही केस दर्ज किया है। यहां दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है। कपिल मिश्रा पर आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़, बीबीएमबी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गणतंत्र दिवस की झांकियों और अन्य मामलों पर भाजपा के पंजाब विरोधी रुख के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के प्रति भगवा पार्टी का रवैया हमेशा दुश्मनी वाला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्य भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज एक अजीबोगरीब स्थिति में घिर गए हैं क्योंकि वे बार–बार झूठ का सहारा लेकर पंजाब के प्रति भाजपा के रवैये को जायज ठहराने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और उसकी लीडरशिप में महान सिख गुरु साहिबान के प्रति सम्मान की भावना कहीं नजर नहीं आती और प्रधानमंत्री को तो कभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस (शहीदी वर्षगांठ) की याद में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता स्वीकार करने का समय भी नहीं था। हर कोई जानता है कि न तो प्रधानमंत्री और न ही भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता या केंद्रीय मंत्री इन कार्यक्रमों में नतमस्तक होने के लिए पंजाब आया। यह सिखों और हमारे महान गुरु साहिबान के प्रति एक तंग और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पंजाब और इसकी सरकार के खिलाफ एक ही पटरी पर चल रहे हैं। ये पार्टियां एक ही दिन अलग–अलग समय पर एक जैसे प्रेस नोट भी जारी करती हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य राज्य सरकार के खिलाफ जहर फैलाना है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर बादल पंजाब के मुद्दों पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये वही नेता हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए सहमति दी थी और जिन्होंने काले कृषि कानूनों के लिए मोदी की प्रशंसा भी की थी। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां पहले नशा तस्करों और गैंगस्टरों को संरक्षण भी देती रहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भी वे गैंगस्टरों को टिकटें दे रहे हैं। पूर्व कांग्रेसी मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर वार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि रंधावा को याद रखना चाहिए कि उनके पिता ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए बधाई दी थी। गुरदासपुर से वर्तमान लोकसभा सदस्य उसी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसने सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक पर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा न होने के कारण विपक्षी दलों के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सबके बावजूद भी मेरी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और सर्वपक्षीय विकास सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में प्राप्तियों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस स्कूलों में अपग्रेड किया जा रहा है और राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण में पहली बार केरल को पछाड़ते हुए देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सरकारी स्कूलों के 848 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा, 265 ने जेईई और 45 ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंसिपलों और शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर, फिनलैंड और अहमदाबाद भेजा जा रहा है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

विस के बजट सत्र से पहले स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई

भुवनेश्वर १६/०२ (संवाददाता): असेंबली के स्पीकर सुरमा पाधी ने सोमवार को एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें मंगलवार से शुरू होने वाले ज़रूरी बजट सेशन को आसानी से और शांति से चलाने के लिए विपक्ष और ट्रेजरी दोनों से सहयोग मांगा गया। स्पीकर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मुकेश महालिंग, बीजू जनता दल की चीफ व्हिप प्रमिला मलिक, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर राम चंद्र कदम और कई दूसरे सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया।

माझी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर महालिंग ने कहा, यह एकमत से तय किया गया कि हाउस आसानी से और सही तरीके से चले। हाउस सेशन के लिए लिस्टेड नियमों, प्रोसीजर और काम के हिसाब से चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सेशन मंगलवार (17 फरवरी) को ओडिशा के गवर्नर हरि बाबू कंभमपति के भाषण के साथ शुरू होगा। 20 फरवरी को, मुख्यमंत्री माझी फाइनेंशियल ईयर 2026ङ्ग27 के लिए सालाना राज्य बजट पेश करेंगे।

महालिंग ने आगे बताया कि ग्रांट की मांगों पर 14 दिनों की चर्चा के बाद, 2026-27 के बजट के लिए एप्रोप्रिएशन बिल 31 मार्च को पेश किया जाएगा। ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, 17वीं ओडिशा असेंबली का छठा सेशन 8 अप्रैल को खत्म होने वाला है। सेशन दो फेज में होगा और इसमें 28 वर्किंग डे होंगे। शेड्यूल के मुताबिक, 17 फरवरी को गवर्नर कंभमपति के भाषण के बाद, हाउस 19 फरवरी तक गवर्नर के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा करेगा।

इस बीच, अपोजिशन लीडर्स ने मीडिया को बताया कि किसानों की परेशानी और कोटिया पर राज्य के स्टैंड जैसे मुद्दे असेंबली में उठाए जाएंगे ताकि सरकार की नाकामियों की ओर ध्यान दिलाया जा सके।

बीजू जनता दल चीफ व्हिप प्रमिला मलिक ने कहा, हम निश्चित रूप से राज्य भर के किसानों की समस्याओं को उठाएंगे, जिसमें मिलर्स द्वारा धान उठाने में देरी और कटनी छतनी (खरीद के दौरान मिलर्स द्वारा गैर-कानूनी कटौती) की लगातार समस्या शामिल है। दूसरी ओर, कांग्रेस CLP नेता कदम ने कहा कि पार्टी शाम को कांग्रेस स्न्ढ्ढ की मीटिंग के बाद अपनी स्ट्रैटेजी तय करेगी।

भुवनेश्वर में संदिग्ध बम बनाते समय छत पर धमाका, 2 की मौत

भुवनेश्वर १६/०२ (संवाददाता): कुछ लोग अपने घर पर बम बना रहे थे। इसी दौरान एक धमाका हुआ। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। दो अन्य घायल हो गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए इस धमाके का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई। 27 जनवरी को दोपहर 2.45 बजे सुंदरपाड़ा इलाके में चार लोगों ने एक घर पर गैर-कानूनी तरीके से बम बनाने की कोशिश की। इसी बीच, इस मौके पर एक बड़ा धमाका हुआ। आग फैलने पर एक महिला और कुछ अन्य लोग भाग गए। चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़्लीडिंग हुई।

उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दो की मौत हो गई। पुलिस ने मरने वालों की पहचान शाहनवाज़ मलिक और उसकी मां के रूप में की है। माझी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता इस बीच, पुलिस इस घटना की जांच कर रही है जिससे स्थानीय स्तर पर हंगामा मच गया है। धमाके वाली जगह से बारूद बरामद किया गया है। इससे शक है कि शाहनवाज़ मलिक, उसका साथी अमिया मलिक, उसकी माँ और एक और आदमी अपने घर में गैर-कानूनी तरीके से बम बना रहे थे। इस बीच, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि शाहनवाज़ का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन्हें शक है कि उसका परिवार किसी साज़िश के तहत बम बना रहा था। उन्होंने कहा कि बम पर और चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच चल रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जांच में जुट गई है। दूसरी तरफ, धमाके से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मशहूर ओडिया सिंगर गीता पटनायक का निधन

कटक १६/०२ (संवाददाता): मशहूर सिंगर गीता पटनायक, जिन्हें ओडिया म्यूज़िक की सबसे मशहूर आवाज़ों में से एक माना जाता है, का शाम को ब्रेन स्ट्रोक के बाद यहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 73 साल की पटनायक को गुरुवार को एक इवेंट में शामिल होने के दौरान बीमार पड़ने के बाद पहले कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बाद में मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनके देवर प्रदोष पटनायक ने बताया कि बाद में उन्हें कटक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रविवार शाम को उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सिंगर का पार्थिव शरीर सोमवार को कटक में उनके घर ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

गीता पटनायक का करियर कई दशकों तक चला और उन्हें मशहूर ओडिया सिंगर अक्षय मोहंती के साथ उनके कोलेबोरेशन के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई पॉपुलर ओडिया गानों में अपनी आवाज़ दी, जिसमें फिल्म जजबार का फुर किना उड़िगाला बानी% भी शामिल है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ब्ह्य्ठ्ठ प्रमुख नवीन पटनायक ने गीता पटनायक के निधन पर शोक जताया। माझी ने ङ्ग पर लिखा, मशहूर गायिका गीता पटनायक के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उनका जाना ओडिशा के संगीत और संस्कृति के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। दुख की इस घड़ी में, मैं दुखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही भगवान श्री जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी मधुर आवाज ने ओडिया संगीत को हर घर तक पहुंचाया, और उनके गाने हमेशा याद किए जाएंगे। प्रधान ने आगे कहा, ओडिशा की मशहूर गायिका गीता पटनायक के निधन की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी और दुखी हूं। उन्होंने ओडिया संगीत की दुनिया में एक खास पहचान बनाई थी। ओडिशा की कला और संस्कृति को बेहतर बनाने में उनका बेमिसाल योगदान अतुलनीय है। उनकी आवाज का जादू आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

22 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार

हाटाडीही १६/०२ (संवाददाता): भुवनेश्वर में खंडगिरी पुलिस ने एक सोशल वर्कर और ब्ह्यठ्ठ लीडर को 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान सुरेश्वरी सागरिका जेना के तौर पर हुई है। वह एक समाजसेवी संस्था जयदुर्गा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है और क्योंझर जिले के हाटाडीही ब्लॉक के जलकालांग गांव की रहने वाली है। खंडगिरी पुलिस ने नंदीपाड़ा पुलिसवालों की मदद से उसे गिरफ्तार किया। सूत्रों ने बताया कि खंडगिरी पुलिस स्टेशन की एक टीम नंदीपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची और उनकी मदद से जेना को उसके घर से पकड़ लिया। बाद में उसे खंडगिरी पुलिस को सौंप दिया गया। नंदीपाड़ा आईआईसी धर्मेंद्र शांति ने कहा कि महिला को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। खंडगिरी आईआईसी अभिमन्यु दास ने कहा कि खंडगिरी पुलिस स्टेशन में कथित 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में एक केस (465/2025) दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, जेना ने जयदुर्गा फाउंडेशन नाम का एक संगठन बनाया था और वह स्थानीय तौर पर एक सोशल वर्कर के तौर पर जानी जाती थी। वह फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। उसकी गिरफ्तारी से इलाके में चर्चा शुरू हो गई है, लोग सोशल वर्क के नाम पर कथित धोखाधड़ी को शर्मनाक बता रहे हैं। धोखाधड़ी के दूसरे मामलों में भी उसके शामिल होने की खबरें हैं, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर उन दावों की पुष्टि नहीं की है।

रायगडा में बाइक-टैंकर की टक्कर में नाबालिग समेत तीन की मौत

रायगडा १६/०२ (संवाददाता): जिले के टिकिरी पुलिस इलाके के नटराज पेट्रोल पंप पर हुए एक सड़क हादसे में एक नाबालिग समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

मरने वालों की पहचान नरेंद्र झोडिया (25), उमाकांत झोडिया (14), और टुनू झोडिया (23) के तौर पर हुई है। वे गोरखपुर जा रहे थे, तभी देर रात उनकी बाइक एक गैर-कानूनी तरीके से पार्क किए गए टैंकर से टकरा गई। टिकिरी पुलिस ने घायलों को बचाया और उन्हें एम्बुलेंस से उषापाड़ा के उत्कल हॉस्पिटल ले गई। एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो अन्य को रायगडा जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। टुनू झारिया की रायगडा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि उमाकांत ने रायगडा जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद, गुस्साए स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश कर रही है।

लापता हुई नवविवाहित महिला मिली

पिपली १६/०२ (संवाददाता):एक बड़ी सफलता के रूप में, ससुराल से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई नवविवाहित महिला अगले दिन खुर्दा के निरकरपुर पुलिस स्टेशन के पास मिली। सूत्रों के अनुसार, लापता महिला कालीघाड़ी गांव के रामचंद्र सामंतराय की बेटी है और उसकी शादी लगभग दो महीने पहले सुनाखला गांव के रबींद्र चंपज़ी से हुई थी। ससुराल वालों ने बताया कि महिला पास की नदी में नहाने गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। बाद में, महिला के परिवार वालों ने चुपुरिगुंगी में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उसकी हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। बाद में, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके और निरकरपुर रेलवे पुल के आसपास के क्षेत्रों से मिली जानकारियों को जुटाकर रविवार को निरकरपुर में लापता महिला का पता लगाया। आगे की जांच जारी है।

डाक अधिकारी ने 50 से ज़्यादा लोगों से 20 लाख रुपये ठगे, मामला दर्ज

केंद्रपाड़ा १६/०२ (संवाददाता): केंद्रपाड़ा के राजकनिका पुलिस स्टेशन के तहत नदी किनारे बरुणा गांव के पोस्ट ऑफिस में 50 से ज़्यादा ग्राहकों से करीब 20 लाख रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में शनिवार को एक ग्रामीण डाक सेवक (ढ्ढष्ठस्) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी, आसिक कुमार महालिक, बुधवार से लापता है। सूत्रों के अनुसार, ये गड़बड़ियां हाल ही में तब सामने आईं जब कई जमाकर्ताओं ने पाया कि उनकी जानकारी के बिना उनके पोस्टल खातों से बड़ी रकम निकाल ली गई है। बताया जाता है कि महालिक ने जमाकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर करके और उनकी पासबुक से बिना इजाज़त पैसे निकालकर अलग-अलग पोस्टल बचत योजनाओं से पैसे निकाले।

जांच में पता चला कि महालिक ने पैसे हड़पने का एक और तरीका भी अपनाया था, जिसमें वह जमा की गई रकम को आधिकारिक पोस्टल लेजर में दर्ज नहीं करता था, जबकि शक से बचने के लिए ग्राहकों की पासबुक में आंकड़े दर्ज कर देता था। पट्टामुंडई ब्रांच पोस्ट ऑफिस के पोस्टल इंस्पेक्टर अंकुश नस्कर ने कहा, कई खाताधारकों से शिकायतें मिलने के बाद, हमने शुरुआती जांच की और पाया कि ढ्ढष्ठस् ने कई ग्राहकों की जमा रकम में हेराफेरी की है। इसके बाद, राजकनिका पुलिस स्टेशन में स्नढ्ढक्र दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ब्हृस् की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। राजकनिका ढ्ढढ्ढष्ट संजय कुमार मल्लिक ने कहा, आरोपी फरार है। उसे पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पट्टामुंडई ब्रांच पोस्ट ऑफिस के पोस्टल इंस्पेक्टर अंकुश नस्कर ने कहा, कई खाताधारकों से शिकायतें मिलने के बाद, हमने शुरुआती जांच की और पाया कि ढ्ढष्ठस् ने कई ग्राहकों की जमा रकम में हेराफेरी की है। इसके बाद, राजकनिका पुलिस स्टेशन में स्नढ्ढक्र दर्ज की गई।

आईजीएच में एक और सफल घुटना प्रतिस्थापना शल्य-चिकित्सा

राउरकेला १६/०२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) में सम्पूर्ण घुटना प्रतिस्थापना (टीकेआर) अब एक नियमित एवं विश्वसनीय प्रक्रिया बन चुकी है। उन्नत अस्थि विज्ञान सम्बंधित समस्याओं के उपचार की उपलब्धता के कारण अब अधिक से अधिक मरीज महंगे इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों की यात्रा करने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही उपचार का विकल्प चुन रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में एक सफल सम्पूर्ण घुटना प्रतिस्थापना (टीकेआर) शल्यचिकित्सा ने 75 वर्षीय महिला को लंबे समय से चली आ रही चलने-फिरने की दिक्कत से मुक्ति दिलाकर उन्हें पुनः सक्रिय जीवन प्रदान किया।

75 वर्षीय मरीज श्रीमती सरला भंज ने आईजीएच में मिले व्यक्तिगत देखभाल और उपचार के लिए चिकित्सा दल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, पिछले आठ से दस वर्षों से मुझे घुटनों में अत्यधिक दर्द और चलने में कठिनाई हो रही थी। इस्पात जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकीय हस्तक्षेप के कारण में फिर से चलने फिरने के काबिल हो गई हूँ।

श्रीमती भंज को 28 जनवरी, 2026 को इस्पात जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया और 30 जनवरी, 2026 को उनका सफलतापूर्वक सम्पूर्ण घुटना प्रतिस्थापना शल्यक्रिया किया गया। उनकी बुज़ुर्ग अवस्था और लंबे समय से घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रहने की स्थिति को देखते हुए यह शल्यचिकित्सा उनके जीवन की गुणवत्ता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई।

यह शल्यचिकित्सा अस्थि विशेषज्ञ शल्यचिकित्सक एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष (अस्थि विज्ञान), डॉ. एस के तिवारी के नेतृत्व में एक समर्पित चिकित्सा दल द्वारा संपन्न की गई। टीम में अस्थि चिकित्सा विभाग के डॉ. शेषकांत राउत एवं डॉ. नमन शामिल थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ. सी के काशी और वरिष्ठ परामर्शदाता, डॉ. स्मिता कुजूर ने एनेस्थीसिया सहयोग प्रदान किया। इस प्रक्रिया में श्री कमलाकर, सुश्री अर्चना तथा अन्य पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कर्मियों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। शल्यक्रिया के बाद होने वाले दर्द, जिससे अधिकांश मरीज आशंकित रहते हैं, को ध्यान में रखते हुए उन्नत दर्द प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया गया। सर्जरी के बाद पुनर्वास एवं स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया फिजियोथेरेपी टीम के मार्गदर्शन में संपन्न हुई, जिसने मरीज को पुनः शक्ति और गतिशीलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह सफल शल्यक्रिया दर्शाती है कि, बुजुर्ग अवस्था में भी सम्पूर्ण घुटना प्रतिस्थापना संभव है। उचित चिकित्सकीय देखभाल के साथ घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित बुजुर्ग मरीज सुरक्षित रूप से यह शल्यक्रिया करवा सकते हैं और अपनी गतिशीलता तथा जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं।

घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस उपास्थि के लगातार घिसने से होने वाली एक आम और दुर्बल करने वाली बीमारी है, जो बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ तेजी से फैल रही है। गंभीर अवस्था में, पूर्ण घुटने का प्रतिस्थापन (टोटल नी रिप्लेसमेंट) अनिवार्य हो जाता है, जिसके लिए विशेष विशेषज्ञता और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

उल्लेखनीय है कि, इस्पात जनरल अस्पताल पिछले दो दशकों से अधिक समय से प्रतिस्थापन सफलतापूर्वक पूर्ण घुटने का प्रतिस्थापन शल्यक्रिया कर रहा है, जिससे मरीजों को उन्नत एवं किफायती अस्थि रोग उपचार उपलब्ध हो रहा है और अब उन्हें दूरस्थ अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने अनुभवी चिकित्सा दल और मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आईजीएच एक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और गतिशीलता ला रहा है। ढ्ढ